शहर की जनता से रिश्ता
छत्तीसगढ़ का पहला मिड-डे अखबार
हिन्दी दैनिक
जो दिखेगा वो छपेगा
03
METRO
» रायपुर, बुधवार 25 मार्च 2020 » चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा

पेज 4
सप्लाई पर असर, अनाज और तेल की कीमतें बढ़ी...

ताजा खबर
संक्षिप्त

विदेश से लौटने की जानकारी छिपाने वालों पर कसेगा शिकंजा

रायपुर। स्वास्थ्य विभाग की सचिव निहारिका बारिक सिंह ने पिछले एक माह के दौरान विदेश से लौटने की जानकारी छिपाने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखा है. स्वास्थ्य सचिव ने पुलिस महानिरीक्षक को लिखे पत्र में कहा है कि नोवल कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. विभाग की जानकारी में यह बात आई है कि विदेश प्रवास से लौटने वाले कई लोग बिना कोई सूचना दिए अपने घरों में चले गए हैं. विभाग के पास उनकी कोई जानकारी नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने पिछले एक माह के भीतर विदेश से लौटने वाले ऐसे यात्रियों जिन्होंने हेल्पलाइन नंबर 104 के माध्यम से जानकारी नहीं दी है, विदेश यात्रा की बात छुपाने वाले ऐसे लोगों के बारे में यदि किसी अन्य माध्यम से जानकारी मिलती है, तो उनके विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 269, 270 व 188 तथा एपेडेमिक एक्ट, 1897 के सेक्शन 3 की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस महानिदेशक से अनुरोध किया है।

आईएएस राजेश कुमार टोप्पो स्वास्थ्य विभाग में ओएसडी बनाए गए

रायपुर। कांग्रेस सरकार आने के बाद लूप लाइन पहुँच चुके आईएसएस राजेश सुकुमार टोप्पो को अब एक नई जिम्मेदारी दी गई है. टोप्पो कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग में ओएसडी बनाए गए हैं। हालांकि इसके साथ वे मंत्रालय सचिव बने रहेंगे. उन्हें कर्तव्यस्थ अधिकारी स्वास्थ्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है।

पुणे में फंसे 64 जवानों का गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने लिया संज्ञान

रायपुर। लॉकडाउन और सीमा सील के स्थिति में पुणे में फंसे छत्तीसगढ़ के 64 जवानों की खबर चलने के बाद गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने संज्ञान लिया है. ताम्रध्वज साहू की पहल के बाद महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारी ने जवानों से बात की और उनकी पूरी सहायता करने की बात कही। गृहमंत्री ने मामले को लेकर ट्वीट कर जानकारी दी. उन्होंने जवानों से आग्रह किया कि वे इस विकट परिस्थिति में धैर्य का परिचय दें। अभी मेरी वहां प्रभारी लीलेश्वर राजपूत से बात हुई और उन्हें भरोसा दिलाया कि हमारी सरकार की कोशिश है, उन्हें वहां किसी भी प्रकार का कष्ट न हों और उन्हें यथाशीघ्र वापस लाने का प्रयास हम कर रहे हैं। ताम्रध्वज साहू ने पुणे में फंसे छत्तीसगढ़ के जवानों से की फोन पर बात कर जाना हालचाल है. गृहमंत्री ने उन्हें यथाशीघ्र वापस लाने के लिए आश्वस्त किया है।

बैंकों में अब लेनदेन सुबह 10.30 से 2.30 तक

रायपुर। कोरोना वायरस के चलते सरकार ने अब बैंक के खुलने और बंद होने को लेकर समय में बदलाव किया है। मालूम होगा कि कोरोना से निपटने के लिए इस समय देश के सभी राज्यों में लॉकडाउन या फिर कर्फ्यू लगा हुआ है। हालांकि कुछ जरूरी सेवाओं को चालू किया गया है। सरकार ने आज सहकारी बैंक के कामकाज को लेकर समय में बदलाव किया है। जारी आदेश के अनुसार अब सोमवार से शुक्रवार तक बैंक में सुबह 10.30 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक ही काम होंगे। वहीं शनिवार को सुबह 10.30 बजे से 12.30 बजे तक काम होंगे। दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश रहेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन को कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। जिसके चलते बेवजह शहर में घूम रहे लोगों को पुलिस पकड़कर सख्ती से कार्रवाई कर रही है।

स्वास्थ्य विभाग की अपील वालंटियर बनकर करें मदद

रायपुर। कोरोना वाइरस का फैलाव रोकने के लिये युद्धस्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आम जनता की सहूलियत का भी पूरी संवेदनशीलता का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हालात को देखते हुए सरकार ने 31 मार्च तक पूरे प्रदेश में लॉक डाउन करने का निर्देश जारी किया है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश की जनता से कोरोना खिलाफ जंग में सहयोग का आह्वान किया है।

कोरोना संक्रमण रोकने सरकार का बड़ा फैसला, लोगों से घरों में रहने की अपील

लॉकडाउन अब 21 दिनों का...

- राज्य सरकार अब गरीबों को मुफ्त देगी दो महीने का राशन
- देशभर में लॉकडाउन की घोषणा होते ही बढ़ी दवा दुकानों में भीड़

जसेरि रिपोर्टर

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार अब गरीबों को दिया जाने वाला राशन मुफ्त में देगी। यह फैसला अप्रेल और मई महीने के लिए किए गए आवंटन को लेकर किया गया है। करीब 65 लाख परिवारों के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्ड हैं। इन्हें यह सुविधा दी जाएगी। इससे पहले ही सरकार ने दो महीने के राशन का स्टॉक जारी कर दिया था। मंगलवार की शाम कोरोनावायरस के संक्रमण को देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन करने की घोषणा की। यह सुनकर प्रदेश के कई हिस्सों में लोग दवा दुकानों की तरफ भागे। दुकानों में भीड़ भी देखी गई। हालांकि केंद्र सरकार ने जरूरी सेवाएं जैसे, किराना, फल-सब्जी, दवा, गैस, पेट्रोल इन चीजों को लॉकडाउन के दायरे से बाहर रखा है। राज्य सरकार ने राशन, सब्जी, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी सहित कई सेवाओं को आवश्यक घोषित कर दिया गया है। इसका भंडारण और कालाबाजारी करने पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने 31 मार्च तक प्रदेश को लॉकडाउन किया था, केंद्र सरकार के इस फैसले की वजह से यह अवधि अब स्वत: ही बढ़ गई है। राशन कार्ड धारकों को अप्रैल और मई माह के चावल का एकमुश्त वितरण किया जाएगा। अंत्योदय, प्राथमिकता और अन्नपूर्णा श्रेणी के राशनकार्ड धारक अप्रैल माह में चावल के साथ नमक और शक्कर भी ले सकेंगे। इसे ही सरकार ने नि:शुल्क बांटने का फैसला किया है।

ये सब वस्तुएं और सेवाएं आवश्यक सेवाओं में की गई शामिल : सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं, धान की मिलिंग, डीजल-पेट्रोल, एलपीजी सहित कई सेवाओं को आवश्यक सेवा घोषित किया गया है। खाद्य विभाग ने राशन, उनके उपार्जन व भंडारण, बारदाने, सल्फास, कीटनाशक, डनेज आदि के संचालन और वितरण को इसमें शामिल किया है। इसी तरह खाद्यान्नों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मिलने वाली वस्तुओं की लोडिंग-अनलोडिंग, धान की मिलिंग करने वाली राईस मिलें, अधिसूचित पेट्रोल, डीजल, सीएनजी पंपों, एलपीजी (घरेलू व व्यवसायिक) को इसमें शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई सेवा जो संबंधित जिला कलेक्टर की ओर से घोषित की जाएगी।

स्वास्थ्य कर्मचारियों को विशेष भत्ता : कोरोनावायरस की रोकथाम के उपायों के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर के औद्योगिक निर्माण के लिए दो डिस्टिलरी को लाइसेंस दिया है। कोरोना के उपचार में लगे स्वास्थ्य विभाग के अमले को विशेष भत्ता देने का फैसला लिया गया है।

मिड्डे मील : अवकाश अवधि में बच्चों को मिड डे में 40 दिन का सूखा दाल और चावल उनके पालकों को स्कूल से प्रदान किया जाएगा। प्राथमिक स्कूल के प्रत्येक बच्चे को 4 किलो चावल व 800 ग्राम दाल और उच्चतर माध्यमिक स्कूल के बच्चे को 6 किलो चावल व 1200 ग्राम दाल दी जाएगी।

आंगनबाड़ी केंद्र : आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए टेक होम राशन वितरण होगा। 3 से 6 वर्ष के समान्य, मध्यम और गंभीर कुपोषित बच्चों को 125 ग्राम रेडी टू ईट प्रतिदिन के मान से 750 ग्राम टेक होम राशन का अनिवार्य रूप से वितरण, शेष हितग्राहियों को भी पात्रता अनुसार रेडी-टू-ईट का वितरण यथावत जारी रहेगा।

लाइसेंस, टैक्स, कोर्ट पेशी : प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में अनुज्ञा, परमिट, लाइसेंस के नवीनीकरण कराने की समय-सीमा एक माह बढ़ा दी गई है। ऐसे ही राजस्व न्यायालयों में प्रकरणों की पेशी एक अप्रैल या उसके बाद होगी। वाणिज्यिक कर विभाग से बाजार मूल्य की पुनरीक्षित दरें अब एक मई को होंगी। वहीं संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक कर दी गई है।

निजी संस्थानों में वेतन के साथ अवकाश : राज्य के सभी निजी संस्थानों, कारखानों, अस्पतालों, मॉल, रेस्टोरेंट आदि के नियोजकों से श्रमिकों व कर्मचारियों की छंटनी नहीं किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कोरोना से पीड़ित होने या अन्य कारणों से बीमार होने पर संवैतनिक अवकाश प्रदान करने और आवश्यकता पड़ने पर घरों से भी कार्य लिए जाने के निर्देश दिए हैं।

कर्फ्यू में बेवजह निकले लोगों पर सख्ती, 70 से ज्यादा गाड़ियां जब्त

समझाइश काम नहीं आई तो अब पुलिस सख्त रुख अपनाने लगी है। बेवजह घरों से निकले लोगों को पुलिस के डंडे पड़ रहे हैं। धमतरी, रायपुर और जगदलपुर में पुलिस ने लोगों को शर्मिंदा करने वाले पोस्टर भी थमाए। इनमें लिखा है- मुझे समाज की चिंता नहीं, मैं बाहर निकलूंगा, बीमारी फैलाऊंगा...। एक पोस्टर में लिखा है- 13 दिन घर पर रहो वर्ना 13 दिन बाद लोग तुम्हारे घर आएंगे। ऐसे पोस्टर खींचकर पुलिस तस्वीरें ले रही है और सोशल मीडिया में इन्हें जारी किया जा रहा है। कर्फ्यू के दौरान सड़क पर घूमने वालों की गाड़ियों को पुलिस ने जब्त कर लिया। 70 से ज्यादा बाइक और 3 कार पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। वाहनों को जब्त करके थाने में रखा गया है, और लोगों को उनके घर भेज दिया गया। सबसे ज्यादा कार्रवाई खमतराई इलाके में हुई। यहां 31 बाइक जब्त की गई है। इसी तरह मौहदापारा, तेलीबांधा, डीडी नगर, नवा रायपुर, मंदिर हसौद, मोवा समेत अन्य इलाके में ऐसी ही कार्रवाई हुई। दुर्ग जिले से शहर को जोड़ने वाली सीमा को भी बंद कर दिया गया है।

विदेशों से आए 27 लोगों की तलाश; रायपुर, दुर्ग जिले की सीमाएं सील, अब होगी एफआईआर

- विधानसभा की कार्यवाही 26 मार्च को, विधायकों के साथ गनमैन के प्रवेश पर लगाई गई रोक

रायपुर (जसेरि)। कोरानावायरस के संक्रमण और लॉकडाउन की अनदेखी के चलते अब छत्तीसगढ़ सरकार सख्त कदम उठा रही है। रायपुर, रायगढ़ और दुर्ग जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया है। वहीं शासन को विदेश से आए 27 लोगों की भी तलाश है। इनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अब स्वासथ्य सचिव ने डीजीपी को पत्र लिखकर कार्रवाई करने को कहा है। सरकार ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 26 मार्च को होने वाली विधानसभा की कार्यवाही में विधायकों के साथ उनके गनमैन के प्रवेश पर रोक लगा दी है।

घर से बाहर निकलने पर परिचय पत्र साथ रखना जरूरी : तमाम बंदिशों के बावजूद लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने एक जिले से दूसरे में हर किसी के आने-जाने पर रोक लगा दी है। वहीं जिले में भी बेवजह घूमने वालों पर अब एफआईआर दर्ज की जाएगी। बाहर किसी जरूरी काम से निकलने के दौरान लोगों को अपना पहचान पत्र साथ में रखना होगा।

13 दिन में विदेश से आए 340 लोग, मिले 313 : पिछले 13 दिनों विदेश से 340 लोग राज्य में पहुंचे हैं, इनमें से 313 लोग मिले हैं। सभी को क्वारनटाइन किया गया है। जबकि अब तक 27 लोगों को खोजा नहीं जा सका है। अब प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ऐसे किसी व्यक्ति की जानकारी मिले, तो टोल फ्री नम्बर 104 पर शिकायत कर सकते हैं। फल-सब्जी, अनाज और तेल की कीमतों में इजाफा हो गया है। कहा जा रहा है कि बाहर से आवक बंद होने के चलते दाम बढ़े हैं। रायपुर के मुख्य बाजार, गोलबाजार की कई दुकानों में अरहर की दाल नहीं मिल रही, कुछ जगहों पर गेहूं के स्टॉक का संकट है।

इस वजह से अनाज में 3 से 4 रुपए प्रति किलो दाम बढ़ गए हैं। खाने के तेल कि डिब्बों के दाम भी 40 से 60 रुपए तक बढ़े हैं। लॉकडाउन के बाद भी बेवजह सड़क पर घूमने वालों को मुंगेली और धमतरी जिले में पुलिस ने समझाइश दी। जब लोग नहीं मानें तो पोस्टर देकर फोटो खिंचवाई।

21 दिनों का लॉकडाउन, कोरोना को हराने का यही एक तरीका

रायपुर (जसेरि)। पूरे देश में 21 दिन तक लॉक डाउन करने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के फैसले का की पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने सराहना की है. रमन सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस को हराने का यही एक मात्र कदम है।

रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के नाम दूसरे संदेश में एक महत्वपूर्ण विषय दूसरे संदेश में हम सबके सामने रखा है। आज रात के 12 बजे के बाद पूरे देश में संपूर्ण ब्लॉक डाउन होने जा रहा है इसका मतलब यह है कि उन्होंने हर व्यक्ति के लिए हर परिवार के लिए हर घर के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दिया जिस का उल्लंघन नहीं होना है। जो जिस शहर में जिस गांव में जिस मोहल्ले में है वहां ही उसको रहना है बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि आज जिस स्तर में आ रहे हैं राष्ट्रव्यापी और विश्वव्यापी जिस प्रकार कोरोना का इफेक्ट बढ़ते जा रहा है उस दृष्टि से इस को हराने का एक ही तरीका है। 21 दिन यदि हम अलग रहेंगे परिवार के साथ रहेंगे भीड़ भाड़ में नहीं जाएंगे तो इंफेक्शन के उस चैन को रोका

जा सकता है, तोड़ा जा सकता है और कोरोना के खिलाफ जीता जा सकता है। रमन सिंह ने आगे कहा कि यह अपील प्रधानमंत्री ने देश के नाम किया है, यह भारत के लोग कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के लोग कर रहे हैं यहां के डॉक्टर कर रहे हैं यहां के सारे लोग कर रहे हैं उसकी तारीफ।

प्रधानमंत्री जी के सारे स्टेप की तारीफ डब्ल्यूएचओ ने भी की है। हम ठीक दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में एक और बड़ा कदम, कड़ा कदम, कठोर कदम, मजबूत कदम यह 21 दिन का टोटल लॉकडाउन। यह अपने आप में अभूतपूर्व कदम है लोगों को तकलीफ होगी मगर इस विश्वव्यापी कोरोना के खिलाफ हम जंग जीत सकते हैं।

प्रधानमंत्री की बात को सभी गम्भीरता से लेवें : विक्रम उसेंडी : भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रदेशवासियों से कोरोना वायरस संक्रमण की चुनौती से निपटने के लिये की गई अपील को गम्भीरता से लेने का विश्वास दिलाया है। भाजपा ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिये प्रदेशवासी 21 दिनों के सम्पूर्ण लॉकडाऊन का पूरे संयम, संकल्प, साहस, धैर्य और अनुशासन के साथ पालन करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेण्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की कोरोना संक्रमण की बढ़ती चुनौती पर चिन्ता एक प्रधानमंत्री के नाते कम, हर एक परिवार के अभिभावक के रूप में ज्यादा है। दो माह से इस वैश्विक महामारी से मुकाबला करने के बाद अबतक निकले निष्कर्षों का सार यही है कि सामाजिक अलगाव (सोशल डिस्टेंसिंग) ही इस बीमारी से हम सबको सुरक्षित कर सकता है और यह अभियान संक्रमण के चक्र को बाधित करने का रामबाण उपाय है।

मुख्यमंत्री सहायता कोष में सहयोग की अपील

विस अध्यक्ष, मंत्रियों-विधायकों ने दिया एक माह का वेतन

रायपुर (जसेरि)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों से अपील की है कि वो इस संकट की घड़ी में दैनिक वेतनभोगी मजदूरों और जरूरतमंदों की आगे आकर मदद करें। इसके लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में आवश्यक सहयोग राशि प्रदान की जा सकती है। मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए भारतीय स्टेट बैंक के खाता नंबर 30198873179, IFSC CODE: SBIN0004286 पर यह सहयोग राशि जमा की जा सकती है।

इन्होंने दिए एक-एक माह का वेतन : कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए युद्ध स्तर पर जूझते राज्य सरकार के कोरोना राहत कोष में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, सांसद ज्योत्सना महंत, वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा और विधायक शैलेष पांडेय ने एक एक माह का वेतन दान किया है।

टीएस सिंहदेव ने दिया तीन माह का वेतन : संकट के इस घड़ी में टीएस सिंहदेव भी कहाँ पीछे रहने वाले थे. उन्होंने अपना तीन माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए दे दिया. सहायता कोष के लिए यह एक बड़ी बात है. क्योंकि किसी भी विधायक ने अभी तीन माह का वेतन कोरोना संकट के बीच अभी नहीं दिया है।

लखमा और विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों ने भी दिया एक-एक माह का वेतन : कोरोना महामारी के इस संकट के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लोगों से मजदूरों और जरूरतमंदों की सहायता की अपील पर आबकारी एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए अपना एक माह का वेतन दिया है। वहीं आबकारी एवं उद्योग विभाग के प्रथम ओर द्वितीय के श्रेणी के अधिकारी दस दिन का और तृतीय श्रेणी के अधिकारी कर्मचारी तीन दिवस का वेतन मुख्यमंत्री कोष को देने का निर्णय लिया है।

कांग्रेस नेता कन्हैया अग्रवाल ने दिया 1 लाख : रायपुर दक्षिण विधानसभा के कन्हैया अग्रवाल ने महामारी कोरोना से निपटने के लिए सरकारी प्रयासों के साथ जन सहयोग की ज़रूरत को महसूस करते हुए कहा की मेरे परिवार ने मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधन कोष में एक लाख रुपए सहयोग देने का निर्णय लिया है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने उक्त जानकारी देते हुए कहा की प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कोरोना को रोकने हर संभव प्रयास कर रही है । सरकार के प्रयासों को सफल बनाने आप सबके सहयोग की आवश्यकता है. उन्होंने कहा की कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालम करते हुए लॉकडाउन को सफल बनाने प्रत्येक नागरिक को सहयोग करना होगा।

कई जिले के एसपी बदले, नीतू कमल सीबीआई के लिए रिलीव

रायपुर (जसेरि)। राज्य सरकार ने कई आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया है. रायपुर जिले के एएसपी प्रफुल्ल ठाकुर को महासमुंद जिले का एसपी बनाया गया है. महासमुंद एसपी जितेंद्र शुक्ला का ट्रांसफर राजनांदगांव किया गया है. वहीं बलौदाबाजार एसपी नीथू कमल को सीबीआई के लिए रिलीव कर दी गई है। बजट सत्र के पहले से ही कई एसपी बदलने की चर्चा थी। कोरोना संक्रमण के कारण लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संभालने के लिए तबादले रोक दिए गए थे, लेकिन मंगलवार रात दर्जनभर एसपी समेत 20 अफसरों के तबादले की सूची जारी की गई है। कई एसपी को बटालियन में कमांडेंट बना दिया गया है, जबकि राजधानी में एडिशनल एसपी सिटी की जिम्मेदारी संभाल रहे राज्य सेवा के अधिकारी प्रफुल्ल ठाकुर को महासमुंद जिले का एसपी बनाया गया है।

अफसर	वर्तमान	नई पदस्थापना
जितेंद्र सिंह मीणा	एसपी कोरबा	एसपी बालोद
बालाजी राव मावार	एसपी रेल	एसपी कोंडागांव
डी. श्रवण	एआईजी पीएचक्यू	एसपी मुंगेली
कमललोचन कश्यप	कमांडेंट तीसरी बटालियन	एसपी बीजापुर
केएल ध्रुव	कमांडेंट 10 वीं बटालियन	एसपी कबीरधाम
अभिषेक मीणा	कमांडेंट जंगल वारफेयर कॉलेज	एसपी कोरबा
एमआर अहीरे	एसपी गरियाबंद	एसपी कांकेर
जितेंद्र शुक्ला	एसपी महासमुंद	एसपी राजनांदगांव
भोजराम पटेल	एसपी कांकेर	एसपी गरियाबंद
दिव्यांग पटेल	एसपी बीजपुर	एसपी बेमेतरा
प्रशांत कुमार ठाकुर	एसपी बेमेतरा	एसपी लौदाबाजार
जेआर ठाकुर	कमांडेंट 17वीं बटालियन	एसपी रेल
प्रफुल्ल ठाकुर	एएसपी रायपुर	एसपी महासमुंद